भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कम मात्रा पाए जाने के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1432. **श्री कपिल सिब्बल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मार्च, 1997 में भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) के गोदामों के अभिलेखों की वास्तविक जांच के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कम मात्रा पायी गयी;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 के अंत तक इसके अभिलेखों में गेहूं, चावल, धान और खराब अनाज की कितनी-कितनी मात्रा दर्शाई गई थी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच के दौरान वास्तव में कितनी-कितनी मात्रा पायी गयी;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के रजिस्टरों के बुक बेलेंस तथा 31.3.1997 के समायोजित वास्तविक बैलेंस में 4.74 लाख टन का अंतर है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(आंकड़े टन में)

जिन्स	भारतीय खाद्य निगम रजिस्टरों के अनुसार बुक बैलेंस	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार समायोजित वास्तविक बैलेंस	अंतर
चावल	90.06	87.30	2.76
धान	6.91	6.40	0.51
गेहूं	17.29	16.68	0.61
क्षतिग्रस्त/घटिया	2.71	1.85	0.86
जोड़	116.97	112.23	4.74

(ग) और (घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां देने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है, परंतु उनकी टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा रखे गए स्टाक का सत्यापन भी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना है। केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा रखे गए खाद्यान्नों का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन करने के बाद खाद्यान्नों के स्टाक में कमियों के बारे में सुस्पष्ट स्थिति सामने आएगी।

गेहूं और खाद्य तेल की मांग

1433. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् 2000 तक देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गेहूं और खाद्य तेल की कुल कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) इसमें से कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आयातित खाद्य तेल और गेहूं की तुलना में देश में उत्पादित खाद्य तेल और गेहूं के मूल्यों में क्या अंतर है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) "कृषि जिन्सों की मांग और आपूर्ति के अनुमान और नौवीं पंचवर्षीय योजना, तैयार करने के लिए कृषि सांख्यिकी में सुधार करने" संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में 6% की वृद्धि दर मानते हुए 2001-02 में गेहूं की मांग 68.50 मिलियन टन और सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि दर मानते हुए 70.25 मिलियन टन मांग होने का अनुमान है। कार्यकारी दल द्वारा गेहूं की राज्यवार मांग का अनुमान नहीं लगाया गया है।

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 1999-2000 के दौरान देश में खाद्य तेल की मांग 84.18 लाख टन होगी। खाद्य तेल की राज्यवार मांग की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के टर्मिनल वर्ष अर्थात 2001-02 के लिए गेहूं आपूर्ति के प्रक्षेपण 75.50 मिलियन टन अनुमानित हैं।

खाद्य तेल उत्पादन की गणना तिलहन उत्पादन के आधार पर की जाती है।

(ग) गेहूं उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नामता एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसके माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

तिलहन/तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(घ) देश में उत्पादित खाद्य तेल के मूल्य और आयातित तेल के मूल्य में निश्चित अंतर नहीं होता है। यह खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति स्थिति, खाद्य तेलों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होता है। यह भी तेल दर तेल भिन्न-भिन्न होता है।

इसी प्रकार देश में उत्पादित गेहूं और आयातित गेहूं के मूल्य में अंतर विभिन्न घटकों जैसे ठेके के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य, गुणवत्ता, भाड़ा प्रभार आदि पर निर्भर करेगा। यह भी किस्म दर किस्म अलग-अलग होता है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं नामतः राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और आयलसीड प्राडक्शन थ्रस्ट प्रोजेक्ट, जो 1989-90 तक चल रही थी, का 1990-91 के दौरान एक एकल योजना नामतः तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। योजना में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध संगरोध उपायों जिसमें पौध संगरोध रसायन और उपकरणों की आपूर्ति तथा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी पर विशेष जोर देने सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है, के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

अच्छा उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान उपायों में तीव्रता लाना।

सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्षों और वनों से प्राप्त होने वाले तिलहनों और चावल की भूसी आदि का समुपयोजन।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना।

आयल पाम विकास के लिए सहायता।

प्रमुख तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित आधुनिकीकरण उपकरणों का और कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क में मिलने वाली रियायतों का पता लगाना।

Presence of Exotic Weeds in imported Australian Wheat

1434. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government imported wheat from Australia in the recent past, if so, the details of wheat imported including the agencies earmarked to import wheat;

(b) whether Government are aware of the excessive presence of serious exotic weed seeds in the Australian wheat as reported in the Hindustan Times dated the October 11, 1998;

(c) whether the CBI has been asked to investigate the matter; and

(d) if answers, to parts (b) and (c) above be in affirmative, the details thereof, including the final outcome of CBI investigation and the action taken against those found guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. State Trading Corporation of India (STC) had imported 14.15 lakh tonnes of wheat from Australia during 1998-99 @ US $ 142.50 PMT (FOB).

(b) Yes Sir. Presence of some weed seeds was detected in the Australian Wheat. Such weed seeds are an intergral part of any foodgrains harvest and it is not unsual to detect weed seeds in any bulk import of foodgrains. The Australian wheat conforms to the provisions of the contract and the specifications laid down in the Prevention